



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2009/कार्तिक 12, 1931

No. 332]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2009/KARTIKA 12, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच प्रारंभ संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

विषय : चीन जन. गण., जापान, कोरिया आर. पी., मलेशिया, रूस, ताईवान तथा थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलि विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन (पी वी सी पेस्ट रेजिन)' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/36/2009-डीजीएडी.—मै. केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड, चेन्नई ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं के अभिज्ञान, मूल्यांकन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण हेतु) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा जाएगा) के अनुसार चीन जन. गण., जापान, कोरिया आर. पी., मलेशिया, रूस, ताईवान तथा थाईलैंड (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलि विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन (पी वी सी पेस्ट रेजिन)' (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी उपाय लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद "पॉलि विनाइल क्लोराइड पेस्ट/इमल्शन रेजिन है" जिसे "इमल्शन पी वी सी रेजिन भी कहा जाता है और पी वी सी पेस्ट रेजिन (जिसे एतदपश्चात् 'संबद्ध उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' कहा जाएगा)" के नाम से जाना जाता है। पी वी सी रेजिन की दो किस्में होती हैं अर्थात् पी वी सी पेस्ट रेजिन और पी वी सी सस्पेंशन रेजिन। पी वी सी सस्पेंशन रेजिन को प्रस्तावित जांच के दायरे और कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। पी वी सी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनाइल क्लोराइड (वी सी एम) से किया जाता है। वी सी एम का उत्पादन ई डी सी के प्रयोग द्वारा किया जाता है तथा ई डी सी के उत्पादन हेतु एक प्रमुख उत्पाद के रूप में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन एवं बिक्री सफेद/ऑफ़ व्हाइट पाउडर के रूप में की जाती है। उत्पाद के गुण-धर्मों का विवरण K मूल्य, स्वाभाविक लसिलेपन,

पार्टिकलसाइज रिटेन्शन, उष्मा ह्रास, प्रारंभिक बी एफ बी इत्यादि के संदर्भ में दिया जाता है। पी वी सी पेस्ट रेजिन के सभी ग्रेड जांच के दायरे एवं कार्यक्षेत्र में आते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का आयात निम्नलिखित सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत किया जा सकता है।

अध्याय/उप शीर्ष	विवरण
अध्याय 39	प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं
उप शीर्ष 39.04	विनाइल क्लोराइड के अथवा अन्य हेलोजनीकृत ऑलेफिन्स के प्रारंभिक स्वरूपों के पॉलिमर्स
चार अंकीय 39 04.22	प्लास्टिसाइज्ड
आठ अंकीय 39 04.22 10	पॉलि (विनाइल क्लोराइड)(पी वी सी) रेजिन (इमल्शन ग्रेड)

ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

घरेलू समान उत्पाद

4. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला रहे हैं।

5. जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को, इस जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान उत्पाद माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग एवं 'स्थिति'

6. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 केमप्लास्ट सन्मार लि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने क्षति एवं लागत संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक द्वारा किया जाने वाला उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है और वह घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है।

7. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 78.9 प्रतिशत बनता है। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि यह आवेदन, पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थों के भीतर आवेदक को 'घरेलू उद्योग' माना जा रहा है।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन गण, जापान, कोरिया आर पी, मलेशिया, रूस, ताईवान एवं थाईलैंड है।

सामान्य मूल्य

9. चीन जन गण के संबंध में आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध। के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने निवेदन किया है कि वह चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस प्रकार आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की संरचित-लागत के आधार पर किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय एवं लाभ शामिल है। आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि थाईलैंड को चीन जन गण का सहोदर देश माना जाए। प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर भी टिप्पणियाँ मांगी हैं।

जहां तक अन्य संबद्ध देशों का संबंध है, आवेदक ने यह निवेदन करते हुए संबद्ध देशों के संदर्भ में सामान्य मूल्य संरचित किया है कि वह संबद्ध देशों में घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं और न ही ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इस जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर प्रथमदृष्ट्या विचार किया है।

निर्यात कीमत

10. आवेदक ने आई बी आई एस द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमतों का निर्धारण किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निर्यात कीमतों में समुद्री मालभाड़े, समुद्री बीमे, पत्तन प्रहस्तन, अंतर्देशीय परिवहन एवं बैंक कमीशन आदि का समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

11. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथमदृष्ट्या इस बात का द्योतक है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

"क्षति" एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने का दावा करते हुए इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह दावा किया गया है कि आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन तथा खपत के सापेक्ष वृद्धि हुई है और आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का अत्यधिक अवमूल्यन हुआ है। आवेदक ने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ, नियोजित पूंजी से आय में आई गिरावट एवं कीमत अवमूल्यन आदि के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आने का दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार इस जांच शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए आवेदक को हो रही "क्षति" के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. पूर्वोल्लिखित पैराग्राफों में किए गए विवेचन के अनुसार प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" तथा पाटन एवं "क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करता है। अतः प्राधिकारी कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि अधिरोपित किया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में कथित पाटन एवं परिणामतः घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" की जांच एतद्वारा शुरू करते हैं।

जांच अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक होगी। तथापि क्षति की जांच अवधि में अप्रैल 2005-मार्च 2006, अप्रैल 2006-मार्च, 2007, अप्रैल 2007 - मार्च 2008 तथा जांच अवधि (पी ओ आई) अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि भी शामिल की जाएगी।

15. संबद्ध ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से उसकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

कमरा सं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।

सूचना प्रस्तुत करना

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी सूचना का अगोपनीय स्मान्तर गोपनीयता के कारणों का ब्यौरा देते हुए प्रस्तुत करें। गोपनीय सूचना के अगोपनीय पाठ अथवा अगोपनीय सारांश में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सार्थक सूचना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ब्यौरा दिया गया हो। ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में यदि ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देंगे।

समय सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय स्मान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

"उपलब्ध तथ्यों" का उपयोग

20. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना जुटाने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिसफारिशों कर सकते हैं, जिन्हें वे उपर्युक्त समझते हों।

3992 G709-2

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (PVC Paste Resin) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand

No. 14/36/2009-DGAD.—M/s. Chemplast Sanmar Limited, Chennai has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) alleging dumping of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (PVC Paste Resin) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as subject countries) and have requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping measures.

Product under consideration

2. The product under consideration is 'Poly Vinyl Chloride Paste/Emulsion Resin' also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin (hereinafter referred to as "subject product" or "subject goods"). There are two types of PVC resin, namely PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. PVC suspension resin is excluded from the ambit and scope of the proposed investigation. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the product are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc. All grades of PVC Paste Resin are within the ambit and scope of the investigation.

3. The product under consideration is falling under Chapter 39. The product under consideration can be imported under the following Customs classifications:

Chapter/Subheading	Description
Chapter 39	Plastics and Articles thereof
Sub Heading 39.04	Polymers of Vinyl Chloride or of other Halogenated olefins in primary forms.

Four Digit 39 04.22	Plasticized
Eight Digit 39 04.22.10	Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Resin (emulsion grade)

The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

Domestic Like Article

4. The applicant has claimed that there is no significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the Indian industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

5. For the purpose of investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as like article to the subject goods imported from subject countries within the meaning of the AD Rules for the purpose of this investigation.

Domestic Industry & 'Standing'

6. The application has been filed by M/s. Chemplast Sanmar Limited, Chennai on behalf of the domestic industry. The applicant domestic producers have provided injury and costing information. As per the evidence available on record, production of the applicant accounts for a major proportion of the domestic production and the same is more than 50% of the Indian production.

7. As per information available on record, the Applicant accounts for 78.97% of the total domestic production. Thus, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and the applicant is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Countries involved

8. The countries involved in the present investigation are China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand.

Normal value

9. In respect of China PR, the applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore the Normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the AD Rules. The applicant has submitted

that they have not been able to get the sufficient information regarding market economy third country for determination of Normal value in case of China PR. Thus, the applicant has claimed the Normal value on the basis of constructed cost of production, including selling general and administration expenses and profits. The applicant has also submitted that Thailand may be treated as surrogate country for China PR. The Authority seeks comments on this issue as well.

As regards other subject countries, the applicant has constructed the normal values in respect of subject countries stating that they were not able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices in the subject countries nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicant for the purpose of this initiation.

Export Price

10. The applicant has determined export prices based on the data compiled by IBIS. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, port handling, inland transportation, and bank commission etc to arrive at net export price at ex-factory level.

Dumping margin

11. There is sufficient evidence that the Normal value of the subject goods in subject countries is significantly higher than the net Export price, prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

'Injury' and Causal Link

12. The applicant has furnished evidence claiming injury as a result of alleged dumping. It has been claimed that the imports have increased in absolute terms and in relation to production & consumption in India; the imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry. The applicant has claimed deterioration in performance of the domestic industry in terms of sales, production, utilization of capacity, market share, profit, return on capital employed and price suppression etc. There is sufficient evidence with regard to 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of this investigation in terms of the AD Rules.

Initiation of Anti Dumping Investigation

13. In view of the foregoing paragraphs, the Designated Authority finds that sufficient evidence of dumping of subject goods from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an

anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of investigation

14. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2008 to 31st March 2009. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and the Period of Investigation (POI) viz. 1st April 2008 to 31st March 2009.

Submission of information

15. The known exporters in subject countries, their government through their Embassy/High Commission in India, the known importers and known users in India to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhawan,
New Delhi - 110107.**

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Submission of information on Non-confidential basis.

17. In terms of Rule 7 of the AD rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority along with the reasons for claiming confidentiality. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

3992 GD-9-3

Time limit

18. Any information relating to this investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address, not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Inspection of Public File

19. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information/evidence submitted by other interested parties.

Use of 'facts available'

20. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority